के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हो सके, अन्यथा, देर सवेर हमारी संपूर्ण न्याय व्यवस्था पर से आम लोगों का भरोसा कम होता चला जाएगा, जो न सिर्फ लोकतंत्र के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए अशुभ होगा। इस स्थिति में सुधार के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए।

श्री राजनीति प्रसाद (बिहार): मैं अपने को इस स्पैशल मैंशन के साथ सम्बद्ध करता हूं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shrimati Hema Malini; not present. Shri Ram Narayan Sahu.

Need for Finance Package for Farmers in the Country

श्री राम नारायण साहू (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन का ध्यान केन्द्र सरकार के अंसेवदनशील व्यवहार की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। केन्द्र ने एक लंबे इंतजार के बाद किसानों को राहत देने के लिए एक पैकेज घोषित किया है, वह भी मात्र 4 राज्यों के 31 जिलों में लागू होगा, जिसके लिए सरकार ने केवल 16,978 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं अर्थात देश के अन्य राज्यों के पीड़ित किसानों को अपनी समस्या से राहत पाने के लिए बीमारी के लाइलाज होने तक इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद ही उपचार होगा।

महोदय, मैं नमन करता हूं देश के उस सच्चे सेवक को जिसने जवानों और किसानों के सम्मान में अपना मस्तक झुकाकर कहा था–"जय जवान जय किसान"। संभवत: वर्तमान सरकार की प्राथमिकताओं में किसान अंतिम व्यक्ति है, अन्यथा इस प्रकार की राहत नीति निर्धारित न होती।

सम्माननीय साथियों, मेरा अनुरोध है कि प्यास से तड़पते को पानी पिलाना अच्छी बात है, परन्तु पानी पिलाने के लिए प्यासे को तड़पने तक इंतजार कराना विवेकपूर्ण नहीं है। अत: मेरा अनुरोध है कि सरकार को गरीब किसानों की दयनीय आर्थिक दशा का न्यूनतम मापदंड निर्धारित करना चाहिए और उस मापदंड में जो भी किसान आए, चाहे वह किसी भी राज्य का हो, उसे आर्थिक सहयोग मिलना चाहिए। जब भी गरीब किसान की ऋण माफी की बात आती है, तो बैंक विशेषज्ञ तर्क देते हैं कि ऐसा करने से किसानों में ऋण न चुकाने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। मैं स्मरण कराना चाहता हूं कि औद्योगिक घरानों की ऋण माफी से उद्योगपतियों में पैसा मारने की प्रवृत्ति नहीं बढ़ी, तो किसान को ही संदेह से क्यों देखा जाता है? आज पूरे भारत में किसानों की हालत खराब है। वह हमारा पेट ही नहीं पालता, बल्कि सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा भी प्रदान करता है। धन्यवाद।

श्री अबू आसिम आज़मी (उत्तर प्रदेश): मैं अपने को इस स्पैशल मैंशन के साथ सम्बद्ध करता हूं।

†[شری ابو عاصم اعظمی "اتر پردیش" : میں اپنے کو اس اسپیشل مینشن کے ساتھ سمبدھ کرتا ہوں۔]

श्री बनवारी लाल कंचाल (उत्तर प्रदेश): मैं अपने को इस स्पैशल मैंशन के साथ सम्बद्ध करता हूँ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Shreegopal Vyas; not present. Shri Vijaykumar Rupani; not present. Dr. Barun Mukherjee

Need to maintain the Status and Standard of the National Library

DR. BARUN MUKHERJEE (West Bengal): Thank you, Sir, for granting me the permission to make the Special Mention.

Sir, the National Library situated in Kolkata bears the traditional, cultural and intellectual heritage of the country. It has its origin in the famous nineteenth century Calcutta Public Library and Fort William College Library, which were eventually merged into the imperial Library in 1903. After Independence, it was christened as the National Library in 1948, and most befittingly, listed in the Constitution as an Institution of National Importance.

Since 1948, all round development and steady progress of the National Library were witnessed for about four decades. But, of late, the users of the National Library have started feeling disappointed at the gradual deterioration of its services. In such a situation, the Government's casual approach to the problems appears to be more disappointing and disturbing. Nineteenth committees have since been formed but many of their recommendations have not been implemented. More than 200 posts are lying vacant, while nine Directors were given charge since 1990. And, in the process, the National Library has failed to act as the leader of libraries in the country as per UNESCO recommendation. To aggravate the situation, the Government has, on certain occasions, planned to shift the National Library from Kolkata or to convert it into an autonomoual institution. The users of the National Library obviously feel that its constitutional position is being undermined.

In such a grave situation, the leading library organizations, along with the employees of the National Library, had organized a convention on 17th November 2006 and adopted a 15-point resolution for the active consideration of the Union Government. I urge upon the concerned Ministry to take immediate measures in the matter and help the National Library to regain its post glorious standing.

†[Transliteration in Urdu Script]